राज्यों में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों के राष्ट्रीय संग्रह के विमोचन के अवसर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उद्घाटन

भाषण - 20 अक्टूबर 2022

सुप्रभात,\ माननीय कोयला और खान मंत्री, \ श्री प्रल्हाद जोशी,\ डिप्टी सीएजी (सरकारी लेखा) और अध्यक्ष, GASAB,\ राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी, \ सलाहकार समिति के विशिष्ट सदस्य और मेरे प्रिय साथियों।\

सबसे पहले, हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने \ और प्रकाशन जारी करने की सहमति के लिए \ माननीय मंत्री जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। \

राज्यों में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर \ संपत्ति खातों के राष्ट्रीय संग्रह के लिए आयोजित यह विमोचन समारोह हमारे लिए गौरव और खुशी का विषय है । \

यह प्रयास, आर्थिक और पर्यावरणीय लेखांकन के एकीकरण की दिशा में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के करीब लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। \

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत भी SDG का हस्ताक्षरकर्ता है। \ हमारा यह प्रयास, देश को SDG के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। \

प्राकृतिक संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। \ यह अंतर-पीढ़ी समता तथा जीविका से संबन्धित अंतर्निहित मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।\

परम्परागत लेखांकन केवल आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए डेटा को कैप्चर करता है \ जबकि पर्यावरणीय आँकड़े अक्सर किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पन्न होते हैं। \

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की अवधारणा आर्थिक सूचकांकों और पर्यावरण के परस्पर संबंधित मुद्दे को मिलाने के लिए एक उत्कृष्ट पहल है, \ इसमें पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के प्रयासों पर होने वाली लागत की लेखांकन भी शामिल है। \

पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया भर में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है \ और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बारे में चिंता भी बढ़ रही है। \

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, \ कई देशों ने \ पर्यावरण लेखांकन पर अलग-अलग आयाम हासिल किये है, \ जिसमें खनिज और ऊर्जा संसाधनों के लेखांकन को प्राथमिकता दी गई है। \

मेरे कार्यालय में, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं व System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) ढांचे की आवश्यकताओं \ और साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण के लिए भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, \ सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (GASAB) ने जुलाई 2020 में \ NRA पर एक Concept Paper के माध्यम से 2030 के SDG लक्ष्य के मद्देनजर इस कार्रवाई की परिकल्पना की थी। \

खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर संपत्ति खातों की तैयारी को पहले लक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दी गई थी \ क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं तथा राष्ट्र निर्माण में इनका उपयोग भी अतिसंवेदनशील है । \

GASAB ने प्रख्यात विषय विशेषज्ञों और हितधारक मंत्रालयों,\ नियामक निकायों के सदस्यों और शिक्षाविदों के साथ गठित एक सलाहकार समिति से \ तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन लिया है। \

भारत में CAG, INTOSAI का सदस्य है, \ जो सभी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, \ जिसने सभी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों को सिफारिश की थी कि \ NRA तैयार करने में सहायता करनी चाहिए। \

चूंकि सीएजी की संस्था को लेखांकन के रूपों पर सलाह देना अनिवार्य है व भारत में सीएजी द्वारा राज्य के खातों का संकलन होता है \ और संघ एवं सभी राज्यों में हमारा ऑडिट होता है,\ हमने यह पहल करने का फैसला किया। \

GASAB, लेखांकन मामलों पर सलाह देने के लिए हमारे तत्वावधान में कार्यरत एक बहु-संगठनात्मक निकाय, इस चुनौती के लिए तैयार हुआ। \

यहां, मैं 2019 में महालेखाकार सम्मेलन के दौरान \ माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्बोधन को याद करना

चाहूंगा\ जिसका संदेश भारत के सीएजी की संस्था को सुशासन के उत्प्रेरक के रूप में आगे आना \ और सीएजी को सीएजी प्लस में बदलना है। \

साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को, शासन का एक अभिन्न अंग बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, \ माननीय प्रधान मंत्री ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में देश की सहायता करने की दिशा में \ सीएजी संस्थानों की तेजी से प्रगति की सराहना भी की थी। \

मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने सभी 28 राज्यों \ और 1 केंद्र शासित प्रदेश,\ यानी जम्मू और कश्मीर\ में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखा तैयार करने का \ पहला लक्ष्य समय सीमा के भीतर, \ यानी 2022 तक सहयोगी प्रयासों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से हासिल कर लिया है। \

राज्यों में तैयार किए गए इन परिसंपत्ति खातों के आधार पर, \ GASAB अन्य संबंधित मुद्दों के साथ-साथ राज्यों में संसाधनों के स्टॉक और प्रवाह वाले संग्रह के साथ सामने आया है। \

संग्रह में प्राकृतिक संसाधनों के समग्र प्रबंधन में और सुधार लाने तथा देय राजस्व की वसूली लक्ष्य की प्राप्ति और संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई है। \

मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यों के परिसंपत्ति खातों का यह संकलन और उसमें दी गयी अनुसंशायें, \ प्राकृतिक संसाधनों के उचित और सतत उपयोग के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए नीति निर्माताओं को \ साक्ष्य आधारित डाटा के माध्यम से सामयिक निर्णय लेने में मदद करेगा । \ इससे समुचित विकास एवं पारिस्थितिक चुनौतियों के बीच समानता और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। \

GASAB ने भविष्य में प्रभावी रूप से परिसंपत्ति खाते तैयार करने में \ राज्यों की मदद करने के लिए दिशानिर्देश \ मानक संचालन प्रक्रियाएं भी विकसित की हैं। \

खनिज समृद्ध राज्यों के खनन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस समारोह के लिए आए हैं। \

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें GASAB द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों तथा SOP के अनुसार परिसंपत्ति खाते तैयार करने की इस प्रथा को जारी रखेंगी। \

हम सिस्टम और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के इस प्रयास का हमेशा समर्थन करेंगे। \

मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए GASAB टीम को बधाई देता हूं। \

मैं परामर्शदात्री समिति के सदस्यों और राज्य सरकारों को भी उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं \ जिसके बिना यह संग्रह संभव नहीं होता। \

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, \ यह संग्रह \ जो माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा जारी किया जाएगा, \ इस देश के नागरिकों एवं खनिज और खनन विभागों को समर्पित है \ ताकी आगे भी इस फॉर्मेट में खनिज संसाधनों का लेखाकंन वार्षिक तौर पर तैयार करें \ और सरकारों को प्राकृतिक संसाधनों का सतत और कुशलता से उपयोग करने में सक्षम बनाए। \

अंत में, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय \ और राज्यों के सभी गणमान्य व्यक्तियों, \ परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं \ जिन्होंने सीएजी की संस्था में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए अपना समय देकर \ इस संग्रह को जारी करने के आयोजन को एक बड़ी सफलता दी है।\

वन्देमातरम !